Office : 2545066
Secy : 2545251 (Fax)
Secy. Resi. : 0291-2701162

RAJASTHAN ADVOCATES WELFARE FUND

C/o THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN
HIGH COURT BUILDINGS, JODHPUR – 342001
e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

No. RAWF/Amend/Cir. No. 2/2012/ Dated: 16/06/2012

CIRCULAR

It is hereby circulated for information of all concerned that the Rajasthan Advocates Welfare Fund Act, 1987 has further been amended and the amendment has come into force w.e.f. 28/05/2012.

As per Amended Act every Advocate shall have to comply with following: -

(i) Shall affix welfare fund stamps/(s) of value Rs. **25/**- (Rs. Twenty Five) only on every Vakalatnama and Memo of Appearance and on other such documents as per section 2(m) of the Act instead of stamp of Value Rs. 10/-.

(ii) After the Amendment, the Members of the fund shall pay annual subscription as mentioned against each. The period of subscription shall be 1st July to 30th June of every year :-

(a) Whose standing is les than five years as an Advocate Rs. 300/- p.a.
(b) Who have completed five years standing but not completed ten years Rs. 750/- p.a.
(c) Who have completed ten years standing or more Rs. 1,250/-p.a.

(iii) The lump-sum amount as stated in proviso of section 16(5) has been increased to Rs. 17,500/- (Previously it was Rs. 10,000/-).

(iv) The Trustee Committee has been empowered to grant upto Rs. 40,000/- as ex-gratia in the cases falling under clause of section 25(i) and Rs. 1,00,000/- falling under clause 25(ii).

(v) The Trustee Committee has also been empowered to grant minimum to Rs. 2,50,000/- to the nominee in case a member of the fund dies (this amendment shall not be applicable in respect of a member who is admitted or readmitted after the age of forty five years).

(vi) The schedule fixed under section 17 has also been increased and a sum of Rs.5,30,000/- shall be granted for the membership of 40 years.

(vii) Shall hold the election timely by the every Bar Association as per its constitution, rules or bye-laws and also shall abide by the instructions or directions issued, from time to time, by the Bar Council of Rajasthan or the Bar Council of India.

It is further informed that the welfare fund stamps shall have to be affixed by Every Advocate irrespective of the fact whether one is a member of the fund or not.

A copy of the Notification dated 28.5.2012 published in Rajasthan Rajpatra of Extraordinary issue Part 4 (kha) is enclosed herewith for ready reference and needful action.

(R.P. Malik)
Secretary

No. RAWF/Amend/Cir. No. 2/2012/1809-1810 Dated: 16/06/2012

Copy forwarded to: -

(1) The Presidents/Secretaries of all the Bar Associations in the State of Rajasthan – with a request to give wide publicity of the circular and send Demand Drafts for purchase of stamps and see that stamp/(s) of value Rs. 25/- is/are affixed on every Vakalatnama.

(2) All the Hon'ble Members of Bar Council of Rajasthan – with a request to impress upon the Advocates to comply and to watch that Advocates should affix welfare fund stamp/(s) of value Rs. 25/-.

Secretary
Bar Council of Rajasthan

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 7, सोमवार, शाके 1934–मई 28, 2012 *Jyaistha 7, Monday, Saka 1934–June 28, 2012*	

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 28, 2012

संख्या प. 4(8) विधि/2/2012.–राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई, 2012 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012

(2012 का अध्यादेश संख्यांक 4)

[राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक 25 मई, 2012 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया]

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः, राजस्थान राज्य विधान-सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 15 का संशोधन.- राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 15), जिसे इस अध्यादेश में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 15 में विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) प्रत्येक बार संगम अपने संविधान, नियमों या उप-विधियों के अनुसार यथा समय निर्वाचन करायेगा और राजस्थान का बार काउन्सिल या भारत की बार काउन्सिल द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या निदेशों का पालन करेगा।" ।

3. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 में,-

(i) उप-धारा (1) का विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (5) में,-

(क) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " 200/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "300/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " 500/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "750/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " 750/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "1,250/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (5) के प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "10,000/-रु." के स्थान पर अभिव्यक्ति "17,500/-रु." प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (5) के द्वितीय परन्तुक में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न " : " प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(v) यथापूर्वोक्त संशोधित द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि यदि चालू वर्ष का वार्षिक अभिदान 30 जून को या उससे पूर्व संदत्त नहीं किया जाता है तो निधि का सदस्य, उस तारीख से जिसको अभिदान देय हो जाता है, बकाया की रकम पर 1.50 रु. प्रति सौ प्रति महीने की दर से ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।"।

4. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) में,-

(i) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो लाख पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान अन्तिम परन्तुक से पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि द्वितीय परन्तुक के उपबन्ध उस सदस्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जिसे पैंतालीस वर्ष की आयु के पश्चात् सम्मिलित या पुन:सम्मिलित किया गया है:"।

5. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 19 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**25. निधि के सदस्य को अनुग्रह अनुदान.-** (1) न्यासी समिति, उसको आवेदन के प्रस्तुत होने पर तथा दावे की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात्, किसी सदस्य को निधि से निम्नलिखित दशा में अनुग्रह अनुदान अनुज्ञात कर सकेगी-

(क) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न, अस्पताल में भर्ती के ऐसे मामले में जिसमें कोई बडी शल्य क्रिया अन्तर्वलित हो; या

(ख) यदि उसकी ओपन हार्ट सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण या एन्जियोप्लास्टी होती है या वह क्षय, कुष्ठ, पक्षाघात, कैन्सर, चित्त-विकृति, एड्स, पैराप्लेजिया या किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित पचास प्रतिशत से अधिक की नि:शक्तता से या ऐसे ही किसी अन्य गंभीर रोग से पीड़ित है।

(2) इस प्रकार अनुज्ञात अनुदान खण्ड (क) के अधीन आने वाले मामलों में 40,000/-रु. और खण्ड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में 1,00,000/-रु. से अधिक नहीं होगा:

परन्तु दावा पांच वर्ष की कालावधि में एक से अधिक बार नहीं होगा।"।

8. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"अनुसूची

(धारा 17 देखिए)

5 वर्ष की सदस्यता	:	19,000/-रु.
6 वर्ष की सदस्यता	:	22,000/-रु.
7 वर्ष की सदस्यता	:	25,000/-रु.
8 वर्ष की सदस्यता	:	28,000/-रु.
9 वर्ष की सदस्यता	:	31,000/-रु.
10 वर्ष की सदस्यता	:	36,000/-रु.
11 वर्ष की सदस्यता	:	41,000/-रु.
12 वर्ष की सदस्यता	:	46,000/-रु.
13 वर्ष की सदस्यता	:	51,000/-रु.
14 वर्ष की सदस्यता	:	56,000/-रु.
15 वर्ष की सदस्यता	:	61,000/-रु.
16 वर्ष की सदस्यता	:	67,000/-रु.
17 वर्ष की सदस्यता	:	74,000/-रु.
18 वर्ष की सदस्यता	:	81,000/-रु.
19 वर्ष की सदस्यता	:	88,000/-रु.
20 वर्ष की सदस्यता	:	95,000/-रु.
21 वर्ष की सदस्यता	:	1,05,000/-रु.
22 वर्ष की सदस्यता	:	1,15,000/-रु.
23 वर्ष की सदस्यता	:	1,25,000/-रु.
24 वर्ष की सदस्यता	:	1,35,000/-रु.
25 वर्ष की सदस्यता	:	1,45,000/-रु.

26 वर्ष की सदस्यता	:	1,62,000/-रु.
27 वर्ष की सदस्यता	:	1,79,000/-रु.
28 वर्ष की सदस्यता	:	1,96,000/-रु.
29 वर्ष की सदस्यता	:	2,13,000/-रु.
30 वर्ष की सदस्यता	:	2,30,000/-रु.
31 वर्ष की सदस्यता	:	2,55,000/-रु.
32 वर्ष की सदस्यता	:	2,80,000/-रु.
33 वर्ष की सदस्यता	:	3,05,000/-रु.
34 वर्ष की सदस्यता	:	3,30,000/-रु.
35 वर्ष की सदस्यता	:	3,55,000/-रु.
36 वर्ष की सदस्यता	:	3,90,000/-रु.
37 वर्ष की सदस्यता	:	4,25,000/-रु.
38 वर्ष की सदस्यता	:	4,60,000/-रु.
39 वर्ष की सदस्यता	:	4,95,000/-रु.
40 वर्ष की सदस्यता	:	5,30,000/-रु."।

मार्गेट आल्वा,
राज्यपाल, राजस्थान।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 28, 2012

No. F. 4 (8) Vidhi/2/2012.–In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan

Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012 (2012 Ka Adhyadesh Sankhyank 4) promulgated by her on the 25th day of May, 2012:–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN ADVOCATE WELFARE FUND (AMENDMENT) ORDINANCE, 2012

(Ordinance No. 4 of 2012)

[Made and promulgated by the Governor on the 25th day of May, 2012]

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Advocate Welfare Fund Act, 1987.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-third Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Advocate Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2012.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In section 15 of the Rajasthan Advocate Welfare Fund Act, 1987 (Act No. 15 of 1987), hereinafter in this Ordinance referred to as the principal Act, after the existing sub-section (2),the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Every Bar Association shall hold the election timely as per its constitution, rules or by-laws and shall

abide by the instructions or directions issued, from time to time, by the Bar Council of Rajasthan or the Bar Council of India.".

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In section 16 of the principal Act,-

(i) the existing proviso to sub-section (1) shall be deleted;

(ii) in sub-section (5),-

(a) in clause (i), for the existing expression " Rs. 200/-", the expression " Rs. 300/-" shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the existing expression " Rs. 500/-", the expression " Rs. 750/-" shall be substituted; and

(c) in clause (iii), for the existing expression " Rs. 750/-", the expression " Rs. 1,250/-" shall be substituted;

(iii) in the first proviso to sub-section (5), for the existing expression "Rs. 10,000/-", the expression "Rs. 17,500/-" shall be substituted;

(iv) in the second proviso to sub-section (5), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(v) after the second proviso, amended as aforesaid, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided also that if annual subscription of current year is not paid on or before 30th June, the member of the Fund shall be liable to pay on the amount of arrear an interest at the rate of Rs. 1.50 per hundred per month from the date on which subscription becomes due.".

4. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 17 of the principal Act,-

(i) in the second proviso, for the existing expression "rupees one lac", the expression "rupees two lacs fifty thousand" shall be substituted; and

(ii) after the existing second proviso and before the existing last proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the provisions of second proviso shall not be applicable in respect of a member who is admitted or readmitted after the age of forty five years:".

5. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 19 of the principal Act, for the existing expression "ten rupees", the expression "twenty five rupees" shall be substituted.

6. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- In sub-section (1) of section 20 of the principal Act, for the existing expression "rupees ten", the expression "rupees twenty five" shall be substituted.

7. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- For the existing section 25 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"25. *Ex-gratia grant to a member of the Fund.-* (1) The Trustee Committee, on an application submitted to it, and after being satisfied about the genuineness of the claim, may allow ex-gratia grant to a member from the Fund-

(a) in case of hospitalization involving a major surgical operation other than that specified in clause (b); or

(b) if he undergoes open heart surgery, organ transplantation or angioplasty or is suffering from tuberculosis, leprosy, paralysis, cancer, unsoundness of mind, AIDS, paraplegia or disablement certified by a Medical Board to be more than fifty per cent or from such other serious diseases.

(2) The grant so allowed shall not exceed a sum of Rs. 40,000/- in cases falling under clause (a) and Rs. 1,00,000/- in cases falling under clause (b):

Provided that the claim shall not be more than once in a period of five years.".

8. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 15 of 1987.- For the existing Schedule to the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**SCHEDULE**

(See section 17)

5 years membership	:	Rs. 19,000/-
6 years membership	:	Rs. 22,000/-
7 years membership	:	Rs. 25,000/-
8 years membership	:	Rs. 28,000/-
9 years membership	:	Rs. 31,000/-
10 years membership	:	Rs. 36,000/-
11 years membership	:	Rs. 41,000/-
12 years membership	:	Rs. 46,000/-
13 years membership	:	Rs. 51,000/-
14 years membership	:	Rs. 56,000/-
15 years membership	:	Rs. 61,000/-
16 years membership	:	Rs. 67,000/-
17 years membership	:	Rs. 74,000/-
18 years membership	:	Rs. 81,000/-
19 years membership	:	Rs. 88,000/-
20 years membership	:	Rs. 95,000/-
21 years membership	:	Rs. 1,05,000/-
22 years membership	:	Rs. 1,15,000/-
23 years membership	:	Rs. 1,25,000/-
24 years membership	:	Rs. 1,35,000/-

25 years membership	:	Rs. 1,45,000/-
26 years membership	:	Rs. 1,62,000/-
27 years membership	:	Rs. 1,79,000/-
28 years membership	:	Rs. 1,96,000/-
29 years membership	:	Rs. 2,13,000/-
30 years membership	:	Rs. 2,30,000/-
31 years membership	:	Rs. 2,55,000/-
32 years membership	:	Rs. 2,80,000/-
33 years membership	:	Rs. 3,05,000/-
34 years membership	:	Rs. 3,30,000/-
35 years membership	:	Rs. 3,55,000/-
36 years membership	:	Rs. 3,90,000/-
37 years membership	:	Rs. 4,25,000/-
38 years membership	:	Rs. 4,60,000/-
39 years membership	:	Rs. 4,95,000/-
40 years membership	:	Rs. 5,30,000/-".

मार्ग्रेटा आल्वा,

Governor of Rajasthan.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

10

Government Central Press, Jaipur.